

वैदेशिक क्षेत्र

भारत का विदेशी (बाह्य) सेक्टर वर्ष 2017-18 में अब तक, काफी समुत्थानशील और सशक्त बना रहा। वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही (एच-1) में भुगतान संतुलन के चालू लेखा घाटे का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.8 प्रतिशत होने का सुखद अनुभव जारी है। वाणिज्य वस्तु के निर्यातों में अप्रैल-दिसंबर 2017 में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उछाल आया, निवल सेवा प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि रही, और वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में निवल विदेशी निवेश बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गया तथा विदेशी कर्ज के सूचकों में सुधार रहा 1 इन प्रमुख सुधारों को कार्यान्वित करते समय प्रारंभिक चुनौतियों से उबरने में बजट में सहायक कार्रवाइयों, विदेशी व्यापार नीति की मध्यावधिक समीक्षा और जीएसटी से संबंधित सामयिक नीति परिवर्तनों से मदद मिली।

वैश्विक आर्थिक परिवेश

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

6.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है और उम्मीद है कि इसकी संवृद्धि दर वर्ष 2016 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2018 में बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो जाएगी जो आईएमएफ द्वारा दिए गए पूर्व प्रक्षेपणों के ऊर्ध्वगामी सुधार को दर्शाता है (सारणी 1) विश्व के

विकास में यह ऊर्ध्वगामी सुधार यूरो क्षेत्र, जापान, उभरते हुए एशिया और रूस में वर्ष 2017 की प्रथम छमाही में आशा. न्वित परिणामों से बेहतर योगदान के कारण रहा है, भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यू के में अधोगामी परिवर्तन रहे हैं। विश्व व्यापार का परिमाण वर्ष 2016 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 4.2 प्रतिशत होने और वर्ष 2018 में 4.0 प्रतिशत होने की आशा है। उपयोगी वस्तुओं (तेल और गैर ईंधन) की कीमतों के भी पिछले वर्षों की गिरावट के

सारणी 1: वैश्विक उत्पादन और व्यापार (माल और सेवाएं) प्रक्षेपणों का सिंहावलोकन

	वास्तविक	प्रक्षेपण			डब्ल्यूईओ अंतर	
		2016	2017	2018	अंतर जुलाई, 2017	प्रक्षेपण
विश्व उत्पादन	3.2	3.6	3.7	0.1	0.1	
विश्व व्यापार परिमाण (माल और सेवाएं)	2.4	4.2	4.0	0.2	0.1	
आयात						
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.7	4.0	3.8	0.0	0.2	
ईएमडीईएस	2.0	4.4	4.9	0.1	0.2	
निर्यात						
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.2	3.8	3.6	-0.1	0.2	
ईएमडीईएस	2.5	4.8	4.5	1.0	0.0	

स्रोत: आईएमएफ, विश्व आर्थिक आउटलुक अद्यतन, अक्टूबर 2017

नोट: ईएमडीईएस-उदीप्यमान बाजार और विकासशील, अर्थव्यवस्थाएं।

प्रतिकूल बढ़ने की आशा की जाती है। आईएमएफ (अक्टूबर 2017) के अनुसार, वैश्विक समुत्थान अभी भी पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि मुद्रास्फीति अधिकतर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी लक्ष्य से नीचे है और उपयोगी वस्तुओं के निर्यातक, विशेषरूप से ईंधन निर्यातक तेल की कीमतों में गिरावट के कारण विफल रहे हैं। यद्यपि अल्पकालिक जोखिम व्यापक रूप से सन्तुलित हैं, फिर भी मध्यावधिक जोखिम अभी भी अधोगामी दिशा में हैं।

भारत के भुगतान संतुलन संबंधी प्रगति

भुगतान संतुलन का सिंहावलोकन

6.2 भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति वर्ष 2013-14 से काफी अच्छी है और वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में चालू खाते के घाटे (सीएडी) में कुछ बढ़ोत्तरी होने के बावजूद तथा द्वितीय तिमाही में चालू खाते में अपेक्षाकृत कमी होने के साथ ही वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में भी भुगतान संतुलन की अच्छी स्थिति के जारी रहने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में भारत के

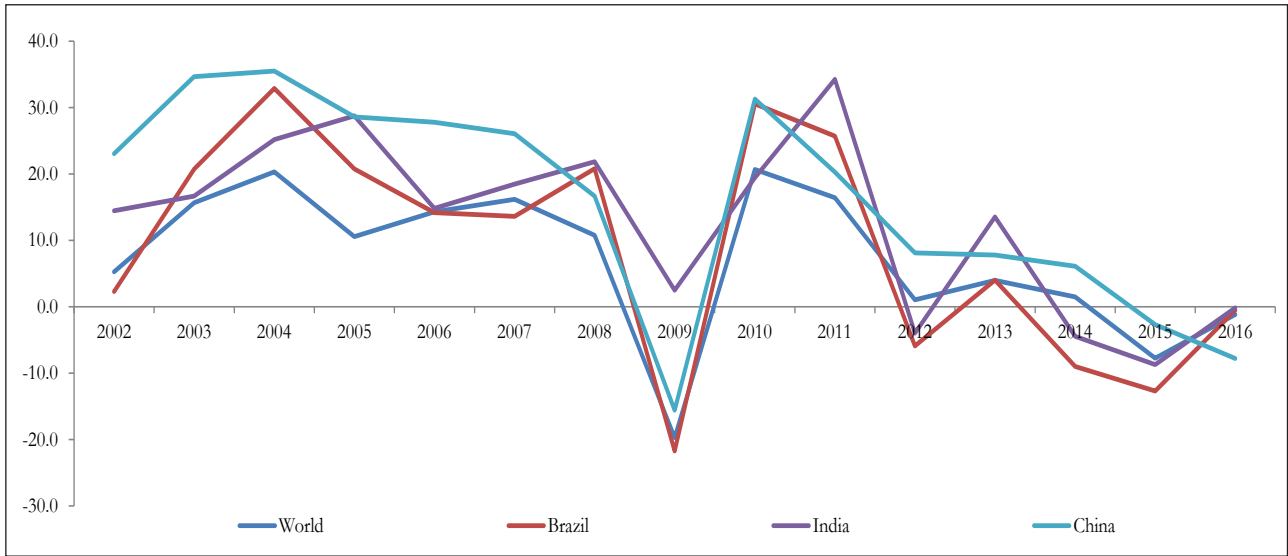
चालू खाते का घाटा 15.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.5 प्रतिशत) था जो वर्ष 2017-18 की द्वितीय तिमाही में तेजी से घटकर 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.2 प्रतिशत) पर आ गया है।' समग्र आधार पर वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में भारत के चालू खाते का घाटा 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.4%) से बढ़कर 2017-18 की इसी अवधि में 22.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.8% हो गया)। निर्यात की तुलना में व्यापारिक आयात में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप मुख्यतः उच्चतर व्यापारिक घाटा (74.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के कारण चालू खाते का घाटा बढ़ गया था। प्रथम तिमाही में जीएसटी कार्यान्वयन के बारे में अनिश्चितता के फलस्वरूप स्वर्णकारों द्वारा क्रय की फ्रंट लोडिंग के कारण सोने के आयात में तीव्र वृद्धि, जिसकी मात्रा दुगने से भी अधिक थी, की वजह से आयातों में वृद्धि हुई। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों (भारतीय बाजार) में वृद्धि होने के फलस्वरूप तेल के आयात संबंधी बिल बढ़ गए—इन तमाम कारणों से आयात में वृद्धि हुई है।

सारणी 2: व्यापार निष्पादन

	(मूल्य US\$ बिलियन में)			प्रतिशत में वृद्धि दर (बाईओवाई)				
	2016-17	2016-17 (अप्रैल से दिस.)	2017-18 (अप्रैल से दिस.)	2016-17	2017-18 (अप्रैल से दिस.)	2016-17 एच-1	2016-17 एच-2	2017-18 एच-1
निर्यात	275.9	199.5	223.5	5.2	12.1	-1.3	11.9	10.8
पीओएल निर्यात	31.5	22.5	26.7	3.1	18.5	-15.0	25.7	16.3
गैर पीओएल निर्यात	244.3	177.0	196.8	5.4	11.2	0.7	10.3	10.1
गैर-पीओएल एवं गैर-रत्नाभूषण निर्यात	200.9	144.7	165.6	4.4	14.5	-1.9	10.8	13.4
आयात	384.4	277.9	338.4	0.9	21.8	-13.3	16.9	25.9
पीओएल आयात	87.0	61.3	76.1	4.8	24.2	-18.1	36.8	17.8
गैर-पीओएल आयात	297.4	216.6	262.2	-0.2	21.1	-11.8	12.2	28.2
स्वर्ण एवं चांदी का आयात	29.4	19.1	29.1	-17.3	52.0	-55.2	29.0	113.8
गैर-पीओएल एवं गैर स्वर्ण स्वर्ण और चांदी का आयात	268.0	197.5	233.2	2.1	18.1	-5.5	10.1	22.3
व्यापार संतुलन	-108.5	-78.4	-114.9	-8.6	46.4	-36.7	29.9	71.8

स्रोत: वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त डाटा के आधार पर

चित्र 1: विश्व और बीआरआईसीएस देशों की गैर-ईंधन निर्यात मूल्य वृद्धि



स्रोत: आईटीसी व्यापार मानचित्र के आंकड़ों के आधार पर।

2017-18 की प्रथम छमाही में चालू खाता संबंधी प्रगति व्यापारिक माल

6.3 बीओपी के अन्य चालू खाते के घटकों में मुख्य रूप से शुद्ध सेवाओं की कमाई और निजी हस्तांतरण की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में सेवाओं के आयात व निर्यात संबंधी कुल प्राप्तियां अधिक थीं। वर्ष 2016-17 की प्रथम तिमाही की तुलना में वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में व्यापार घाटा बढ़ गया है, अदृश्य संतुलन में मामूली सुधार होने और शुद्ध पूंजी प्रवाह में विदेशी निवेश और बैंकिंग पूंजी का वर्चस्व चालू खाते के घाटे संबंधी वित्त में पर्याप्त रहा जिसके फलस्वरूप वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि रकम में वृद्धि हुई।

6.4 वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही में वस्तुओं का आयात (भुगतान संतुलन के आधार पर) 22.1 प्रतिशत बढ़ गया जबकि उपर्युक्त की तुलना में निर्यात वृद्धि 11.3 प्रतिशत थी। सीमा शुल्क आधार पर यह वृद्धि क्रमशः 25.9 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत थी। सीमा शुल्क आयात के आधार पर पीओएल के आयात में 17.8 प्रतिशत की वृद्धि और सोने तथा चांदी के आयात में 113.8 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण कुल आयात में उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। (सारणी 2)

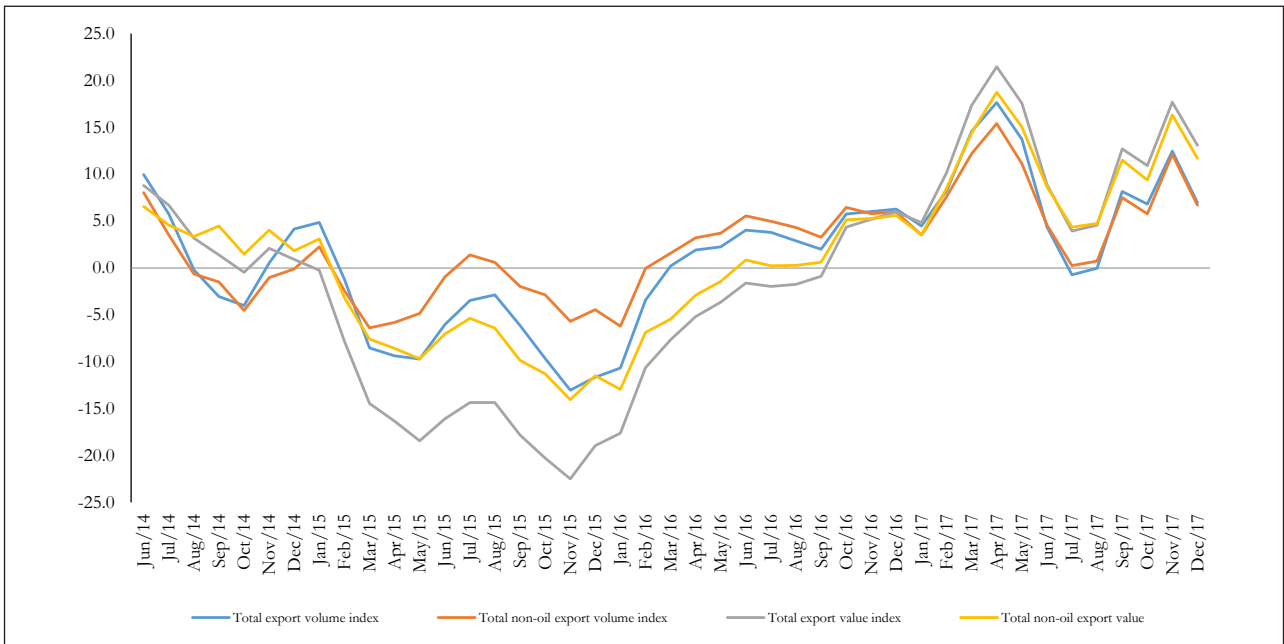
6.5 वर्ष 2013-14 में भारत का वस्तु निर्यात (सीमा शुल्क आधार पर) 314.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। निर्यात वृद्धि में गिरावट के वैश्विक रुझान के फलस्वरूप वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में भारत की निर्यात वृद्धि में

भी क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत की गिरावट आई।

6.6 वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में -1.3 प्रतिशत की दर से भारतीय निर्यात की वृद्धि लगातार ऋणात्मक रही है। किंतु 2016-17 की दूसरी छमाही में, भारतीय निर्यात में बेहतर परिणाम देने वाली 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिससे निर्यात बढ़कर 275.9 बिलियन \$ हो गया है। 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में निर्यात में पुनः 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय निर्यात वृद्धि (गैर-ईंधन) जो सामान्यतः विश्व निर्यात वृद्धि (गैर-ईंधन) की अपेक्षा उच्चतर रही है, वर्ष 2014 में ऋणात्मक हो गई थी और तब से विश्व निर्यात वृद्धि (गैर-ईंधन) की अपेक्षा निम्न या इसके आस-पास ही रही। अन्य बीआरआईसीएस देशों की वृद्धि दर भी कमोबेश इसी प्रकार का रुझान दर्शाती है। (चित्र 1)

6.7 वर्ष 2016-17 में भारत की धनात्मक वृद्धि दर पी. ओएल और गैर-पीओएल दोनों प्रकार के निर्यातों में क्रमशः 3.2 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि के कारण हुई है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-दिसंबर) निर्यातों में वृद्धि 12.1 प्रतिशत थी जिसके अंतर्गत पीओएल और गैर-पीओएल वृद्धि क्रमशः 18.5 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत रही है। भारत की निर्यात परिमाण वृद्धि (3 एमएमए) जोकि मार्च 2016 के बाद से धनात्मक स्थिति में आ गयी है, ने अप्रैल 2017 तक धनात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है किंतु यहां से इसमें कमी की शुरुआत होते देखी गई है, फिर भी यह धनात्मक स्थिति में ही बनी रही है। अगस्त, 2017 से इसमें बढ़ोत्तरी हुई है तथा निर्यात मूल्य वृद्धि में 29.2 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि के

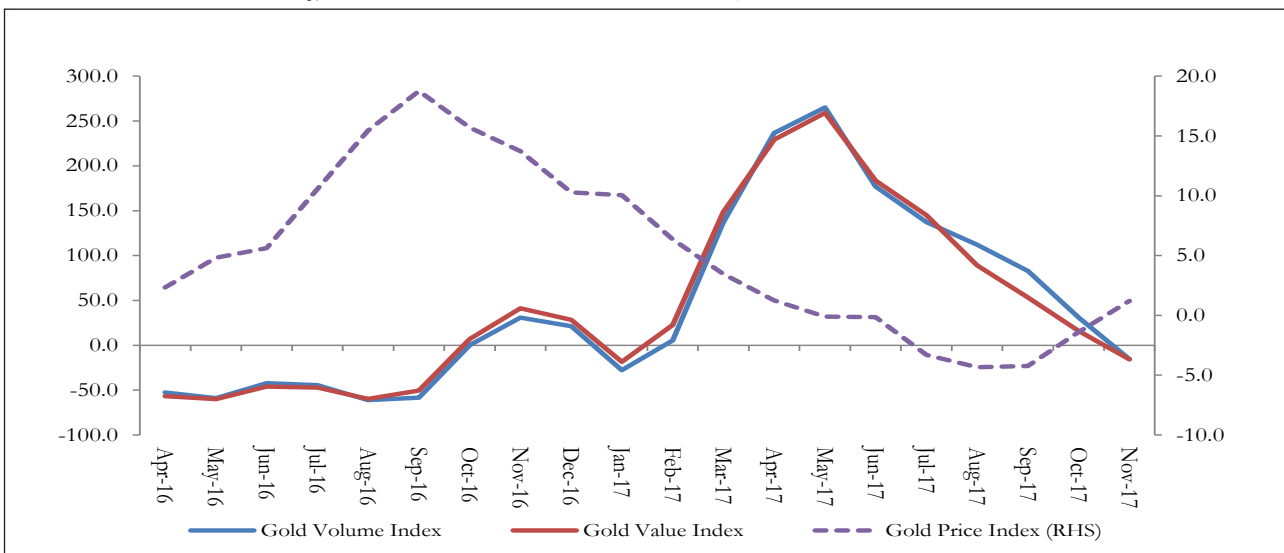
चित्र 2: निर्यातों के मूल्य/परिमाण सूचकांक में वृद्धि: 3 एमएमए (%) 2013-14=100



स्रोत: आंतरिक परिकलन/डीजीसीआई एंड एस के मासिक व्यापार संबंधी आंकड़े, अंतरराष्ट्रीय मूल्य सूचकांक के डॉलर में परिकलित करने हेतु विश्व बैंक की मासिक पिंक-शीट तथा थोक मूल्य सूचकांक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; रुपया सूचकांक को डॉलर सूचकांक में बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय दर।

टिप्पणी: 3 एमएमए-माह के अंत में सूचित 3 माह का चल औसत।

चित्र 3: स्वर्ण परिमाण/मूल्य आयात और स्वर्ण की कीमत में वृद्धि, 3 एमएमए (प्रतिशत) (2013-14=100)



स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के मासिक डाटा से परिकलित

साथ, इसमें नवंबर, 2017 में 21.6 प्रतिशत उतार-चढ़ाव के साथ तीव्र वृद्धि हुई है। तथापि, दिसम्बर में निर्यात मात्रा की वृद्धि दर और मूल्य सूचकांक में क्रमशः 4.7% और 12.4% की गिरावट दर्ज की गई। गैर-तेल निर्यात परिमाण सूचकांक में ऐसी ही प्रवृत्ति बनी रही है। (चित्र 2)।

6.8 पण्यवस्तु आयातों में भी गिरावट आई है और वर्ष 2012-13 के 490.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च आयात की तुलना में वर्ष 2015-16 में 381.0 अमेरिकी डॉलर का ही आयात हुआ है और वर्ष 2016-17 में 0.9 प्रतिशत की हल्की वृद्धि के साथ 384.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का

चित्र 4: आयातों के मूल्य/परिमाण सूचकांक में वृद्धि 3 एमएमए (%) 2013-14=100



स्रोत: 2 के लिए वही

पण्यवस्तु आयात हुआ है। वर्ष 2016-17 में, स्वर्ण और रजत के आयातों में 17.3 प्रतिशत की कमी के बावजूद, आयातों के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण पीओएल आयातों में वृद्धि और गैर-पीओएल तथा गैर-स्वर्ण एवं गैर-रजत आयातों, जोकि वर्ष 2015-16 में गिर गए थे, में लघु वृद्धि थी। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवंबर) में, आयातों में वृद्धि 24.2 प्रतिशत थी। पी.ओएल आयात वृद्धि 21.8 प्रतिशत थी जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि थी। स्वर्ण एवं रजत आयातों में 52.0 प्रतिशत की वृद्धि के कारण गैर-पीओएल आयातों ने 21.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि गैर-पीओएल और गैर-स्वर्ण एवं रजत आयातों में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सितंबर 2017 से स्वर्ण आयात की परिमाण की वृद्धि में गिरावट के कारण सितंबर, 2017 से स्वर्ण आयात मूल्य वृद्धि में गिरावट आई है। स्वर्ण आयात मूल्य सूचकांक स्वर्ण परिमाण सूचकांक के साथ-साथ चल रहा है (चित्र 3)।

6.9 कुल आयात परिमाण सूचकांक और तेल से इतर स्वर्णोत्तर आयात परिमाण सूचकांक में वृद्धि (3 एमएमए), जिसमें जनवरी-फरवरी 2017 तक उछाल आया था उसमें मई 2017 से गिरावट आना प्रारंभ हुआ भले ही यह दिसम्बर 2017 तक सकारात्मक क्षेत्र में बनी रही (चित्र 4)

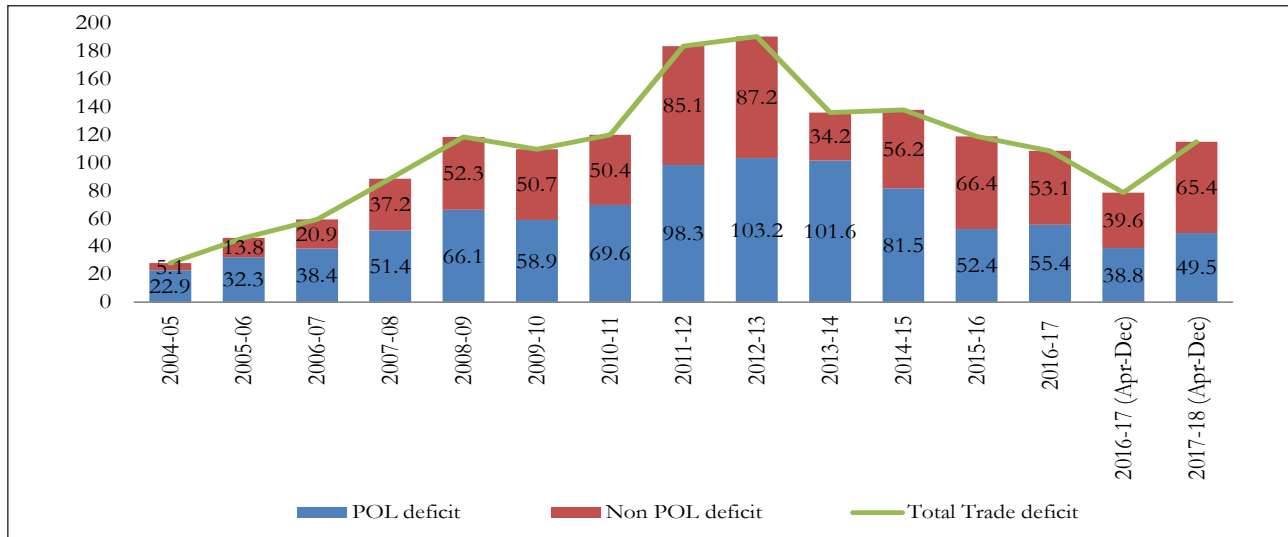
व्यापार घाटा

6.10 सीमा शुल्क आकलन के आधार पर भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2014-15 से लगातार गिरता जा रहा था।

किन्तु वर्ष 2016-17 की पहली छःमाही में जो घाटा 43.4 बिलियन अमेरिकी डालर था वह वर्ष 2017-18 की पहली छःमाही में बढ़कर 74.5 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2016-17 में 108.5 बिलियन अमेरिकी डालर था और पीओएल घाटे तथा गैर पीओएल दोनों प्रकार के घाटों में कमी आई थी। वर्ष 2017-2018 (अप्रैल-दिसम्बर) में व्यापार घाटा (सीमा शुल्क आधार पर) 46.4 प्रतिशत बढ़कर, पीओएल घाटे में 27.4 प्रतिशत की वृद्धि तथा गैर पीओएल घाटे में 65.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ से 114.9 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया (चित्र 5)

6.11 भारत के व्यापारिक भागीदारों में से चीन, स्वीटज़रलैंड, सउदी अरब, ईराक और दक्षिण कोरिया वे शीर्ष 5 देश हैं जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन ऋणात्मक है जबकि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बंगला देश, नेपाल और यू.के. वे शीर्ष 5 देश हैं जिनके साथ भारत का व्यापार संतुलन अधिशेष है। चीन ऐसा मुख्य देश है जो भारत के कुल व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार है। भारत के कुल व्यापार घाटे में चीन की भागीदारी वर्ष 2012-13 में 20.3 प्रतिशत की थी जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 47.1 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2017-18 (अप्रैल-सितंबर) (सारणी-3) में बढ़कर 43.2 प्रतिशत हो गई। चीन से भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं में टेलीफोन हो जिसमें मोबाइल ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, डायोड तथा अन्य सेमी कंडक्टर डिवाइसों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों तथा रासायनिक उर्वरक आदि

चित्र 5: पीओएल और गैर पीओएल कुल घाटा (बिलियन अमेरिकी डालर)



स्रोत: वाणिज्य विभाग से प्राप्त आंकड़े के आधार पर

सारणी: द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष/घाटा (बिलियन अमेरिकी डालर)

		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 H1
देश जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष में है	अमेरिका	11.0	16.6	20.6	18.6	19.9	11.9
	संयुक्त अरब अमीरात	-2.8	1.5	6.9	10.8	9.7	4.0
	बंगला देश	4.5	5.7	5.8	5.3	6.1	3.3
	नेपाल	2.5	3.1	3.9	3.5	5.0	2.6
	यू.के.	2.3	3.7	4.3	3.6	4.9	2.2
देश जिनके साथ भारत का व्यापार घाटा है	चीन	-38.7	-36.2	-48.5	-52.7	-51.1	-32.1
	स्विटजरलैंड	-31.0	-17.5	-21.1	-18.3	-16.3	-9.2
	सऊदी अरब	-24.2	-24.2	-16.9	-13.9	-14.9	-7.3
	इराक	-18.0	-17.6	-13.4	-9.8	-10.6	-5.0
	द. कोरिया	-8.9	-8.3	-8.9	-9.5	-8.3	-6.7
कुल व्यापार घाटा		-190.3	-135.8	-137.6	-118.7	-108.5	-74.3

स्रोत: वाणिज्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गई गणना

शामिल हैं। भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्य वस्तुएं सूती धागा, तांबा, शुद्धिकृत और अशुद्धिकृत तांबा, पीओएल वस्तुएं, ग्रेनाइट, एल्यूमिनियम अयस्क, अन्य निर्धारित सब्जियां और तेल, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कपास, पोलिमेर और लौह अयस्क आदि हैं। स्विटजरलैंड के मामले में व्यापार घाटे का मुख्य कारण सोने का आयात है। पिछले

दो वर्षों के दौरान घाटे में गिरावट आयी है इसके अतिरिक्त इसके एक भाग को निर्यात में प्रयोग किया जाता है। सऊदी अरब और ईराक के मामले में घाटे का कारण कच्चे तेल का आयात करना है जबकि द. कोरिया के मामले में इसका कारण विद्युत उपकरणों एवं मशीनों तथा लोहा और इस्पात का आयात है।

अदृश्य मदे (इनविजिबल्स)

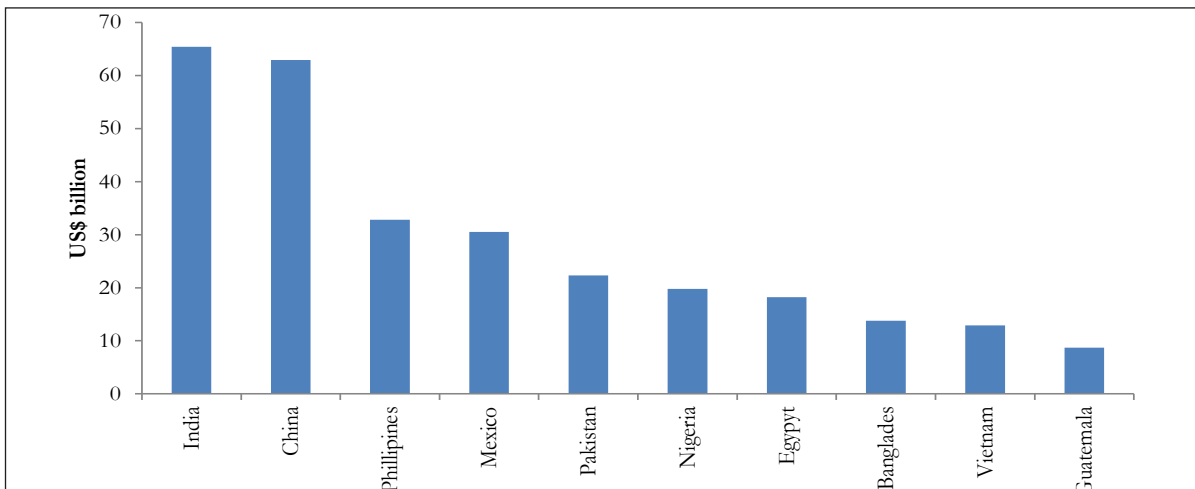
6.12 वर्ष 2014-15 में जो कुल अदृश्य अधिशेष 118.1 बिलियन अमेरिकी डालर था जो वर्ष 2015-16 में गिरकर 107.9 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया और वर्ष 2016-17 में गिरकर 97.1 बिलियन अमेरिकी डालर पर आ गया। कुल सेवाओं और कुल निजी अंतरणों में वृद्धि के साथ जो कुल अदृश्य अधिशेष वर्ष 2016-17 की पहली छःमाही में 45.6 बिलियन अमेरिकी डालर था वह वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में बढ़कर 52.5 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया।

6.13 मुख्यतः यात्रा और दूर संचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं से हुई कुल आय में वृद्धि के कारण वर्ष 2017-18 की पहली छःमाही के दौरान वाई-ओ-वाई आधार पर कुल सेवा प्राप्तियों में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 की पहली छःमाही के दौरान विदेशी पर्यटकों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि, के कारण कुल यात्रा प्राप्तियों में दुगुने से भी अधिक वृद्धि हुई है। अमेरिकी वीजा नीतियों के कठोर होने से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में अनिश्चितताओं के बावजूद वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निजी अंतरण प्राप्तियां जो मुख्यतः विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों द्वारा जमा कराई गई राशि को दर्शाती है, पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान 33.5 बिलियन अमेरिकी डालर से इन निजी अंतरण प्राप्तियों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

6.14 भारत एक प्रमुख सीमा-पार प्रेषित धन प्राप्तकर्ता रहा है और विश्व बैंक (अक्टूबर 2017) के अनुसार, 2017 में

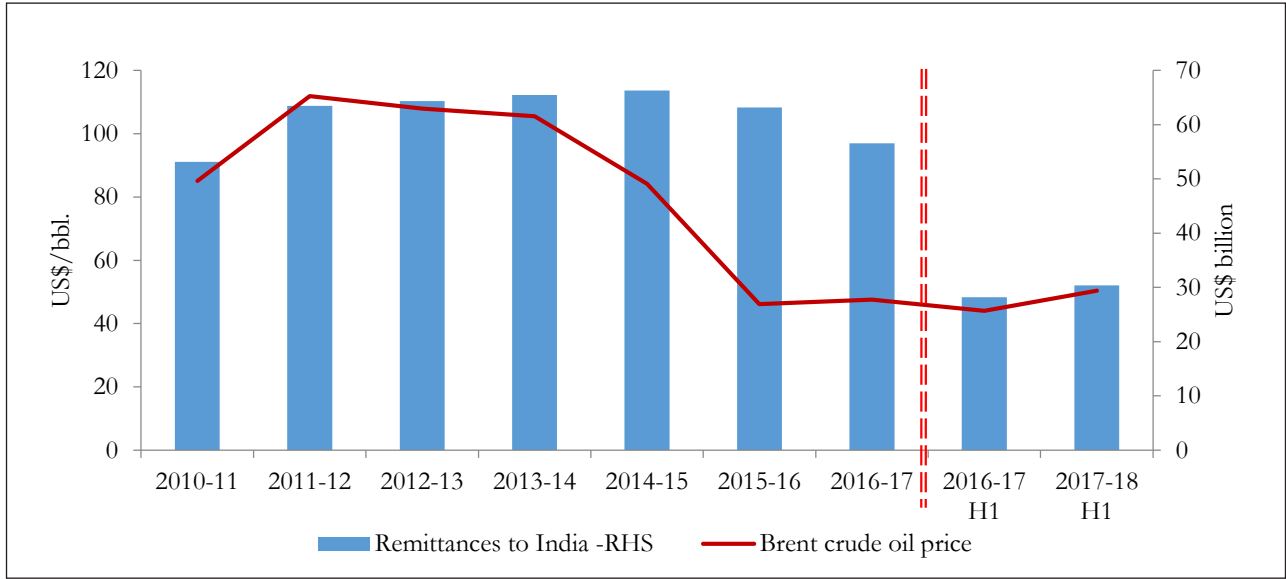
भारत प्रेषित धन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बना रहेगा तथा इसके बाद प्रेषित धन प्राप्त करने वाले देशों में चीन, फिलीपींस और मैक्सिको जैसे देशों का नाम है। हालांकि, भारत के निजी (कुल) अंतरण अंतर्वाह में गिरावट आई है। 2015-16 में 6.1 प्रतिशत तथा 2016-17 में 6.5 प्रतिशत तक इसमें गिरावट आ गई है। इस गिरावट का एक मुख्य कारण स्रोत देशों, विशेषकर जी.सी.सी. (खाड़ी सहकारिता परिषद) के देशों में मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट के कारण श्रम बाजार का सीमित हो जाना है। 2014-15 में कुल निजी अंतरण 69.8 बिलियन अमेरिकी डालर था, जो 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः 65.6 मिलियन अमेरिकी डालर और 61.3 बिलियन अमेरिकी डालर तक नीचे गिर गया। विश्व बैंक, (अक्टूबर, 2017) के अनुसार, सऊदी अरब (भारत का तृतीय सबसे बड़ा प्रेषित धन भेजने वाला देश) को प्रवास गमन करने वाले भारतीय श्रमिकों की संख्या जो 2015 में 3.0 लाख थी वह 2016 में घट कर 1.6 लाख ही रह गई और संयुक्त अरब अमीरात (जहां से भारत में अधिकांश अंतरणों का अंतर्वाह होता है) में यह संख्या 2015 की 2.2 लाख से घटकर 2016 में 1.6 लाख रह गई। 2015 में भारतीय श्रमिकों का कुल बाह्य-प्रवाह 7.8 लाख था जो 2016 में घटकर 5.1 लाख हो गया है। यू.एस.ए. में विदेशी श्रमिकों को किराए पर लिए जाने के प्रतिमानों को कठोर कर देने, जी.सी.सी. देशों में श्रम बाजार का समायोजन करने तथा प्रवास-विरोधी भावना उत्पन्न होने जैसे संरचनात्मक कारणों के कारण बहुत से स्रोत देशों में काफी नकारात्मक जोखिम उत्पन्न हो गई है।

चित्र-6: 2017 में प्रेषित धन प्राप्तकर्ता



स्रोत: प्रवास और धन-प्रेषण पर विश्व बैंक रिपोर्ट, अक्टूबर 2017
टिप्पणी: ये 2017 का अनंतिम प्राक्कलन है।

चित्र 7 : ब्रेट कच्चे तेल की कीमत की तुलना में भारत को किया गया प्रेषण



Source : World Bank Pink Sheet data for Brent Crude oil price and RBI for Net Remittances

6.15 भुगतान-शेष आंकड़ों के अनुसार, कुल निजी अंतरण अंतर्वाह में सामान्य वृद्धि रही है जो 2016-17 के ३१ में 30.4 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2017-18 के ३१ में 33.5 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है। इसके आगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्थान के कारण प्रेषित धन का प्रवाह जो 2016 में 62.7 बिलियन अमेरिकी डालर था, वह 2017 में 4.2 प्रतिशत बढ़कर 65.0 बिलियन अमेरिकी डालर हो जाने का अनुमान है। (विश्व बैंक, अक्टूबर 2017)। चूंकि इनमें साथ-साथ उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए कच्चे तेल की कीमत में होने वाली सामान्य वृद्धि भी धन प्रेषण को बढ़ा सकती है। (चित्र 7)

6.16 निवल निवेश आय के आधार पर बाहिर्वाह जो विगत दो वर्षों में संवर्धित होता रहा है, का बाहिर्वाह स्तर 2016-17 की प्रथम छःमाही में 14.9 बिलियन अमेरिकी डालर रहा है, और यह 2017-18 की प्रथम छमाही में बढ़कर 15.3 अमेरिकी डालर हो गया।

भुगतान शेष का पूंजी/वित्त खाता, 2017-18 का प्रथम छमाही

6.17 2017-18 की प्रथम छःमाही में एफडीआई के अंतर्वाह में गिरावट के होते हुए भी, भारत में पोर्टफोलियो निवेश में त्वरित उत्थान के कारण निवल विदेशी निवेश में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। 2017-18 की दूसरी तिमाही में एफडीआई के मध्यम प्रवाह के कारण 2017-18 के प्रथम छःमाही में वर्ष 2016-17 की प्रथम छःमाही की

अपेक्षा एफडीआई प्रवाह में 6.3 प्रतिशत का संचयी हास हुआ है। किंतु, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में 78.0 प्रतिशत की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यहां 2016-17 की प्रथम छःमाही में 8.2 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2017-18 की प्रथम छःमाही में 14.5 बिलियन अमेरिकी डालर की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई जो घरेलू अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। पूंजीगत प्रवाहों के अन्य प्ररूपों में मध्य विदेशी ऋण और बैंकों द्वारा विदेशी परिसंपत्तियों के परिसमापन से 6.3 बिलियन अमेरिकी डालर की निवल बैंकिंग पूंजी की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के निवल भुगतान के कारण 2017-18 की प्रथम छःमाही में 1.5 बिलियन अमेरिकी डालर का बाहिर्वाह दर्ज किया गया। सीएडी की अपेक्षा उच्चतर शेष निवल पूंजीगत प्रवाह सहित भारतीय विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (बीओपी के आधार पर) में वर्ष 2016-17 की प्रथम छःमाही में दर्ज की गई 15.5 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि की तुलना में 2017-18 की प्रथम छःमाही में 20.9 बिलियन अमेरिकी डालर की निवल अनुवृद्धि हुई। (सारणी 4)।

व्यापार विन्यास

6.18 2016-17 में निर्यात वृद्धि वस्त्र और संबद्ध उत्पादों और चर्म एवं चर्म-विनिर्माताओं के सिवाय प्रमुख श्रेणियों में सकारात्मक वृद्धि के साथ काफी व्यापक थी। 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में, प्रमुख सेक्टरों के बीच, इंजीनियरी वस्तुओं

सारणी 4: भुगतान शेष, अमेरिकी डालर मिलियन

क्रम सं.	मद	(US\$ million)					
		2012-13	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 प्रथम छ:माही	2017-18 प्रथम छ:माही
1	2	3	4	5	6	7	8
I	चालू लेखा						
1	निर्यात	3,06,581	3,16,545	2,66,365	2,80,138	1,34,029	1,49,211
2	आयात	5,02,237	4,61,484	3,96,444	3,92,580	1,83,476	2,24,003
3	व्यापार शेष (1-2)	-1,95,656	-1,44,940	-1,30,079	-1,12,442	-49,448	-74,792
4	अदृश्य (निवल)	1,07,493	1,18,081	1,07,928	97,147	45,580	52,548
	(क) सेवा	64,915	76,529	69,676	67,455	32,040	36,706
	(ख) आय	-21,455	-24,140	-24,375	-26,291	-14,363	-14,257
	(ब) अन्तरण	64,034	65,692	62,627	55,983	27,903	30,098
5	माल और सेवाएं शेष	-1,30,741	-68,411	-60,402	-44,987	-17,408	-38,086
6	चालू खाता शेष (3+4)	-88,163	-26,859	-22,151	-15,296	-3,868	-22,244
II	पूंजीगत लेखा						
	पूंजीगत लेखा शेष	89,300	89,286	41,128	36,482	20,016	42,141
	i. विदेशी सहायता ¹ (निवल)	982	1,725	1,505	2,013	605	691
	ii. बाह्य वाणिज्यिक उधार (निवल)	8,485	1,570	-4,529	-6,102	-3,402	-1,514
	iii. अल्पकालीन उधार	21,657	-111	-1,610	6,467	-493	4,575
	iv. बैंकिंग पूंजी (निवल) जिसमें	16,570	11,618	10,630	-16,616	-6,754	6,340
	अनिवासी जमा (निवल)	14,842	14,057	16,052	-12,367	3,465	1,948
	v. विदेशी निवेश (निवल) जिसमें	46,711	73,456	31,891	43,224	29,035	34,088
	(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवल निवल)	19,819	31,251	36,021	35,612	20,881	19,570
	(ख) निवेश सूची (निवल)	26,891	42,205	-4,130	7,612	8,154	14,518
	vi. अन्य प्रवाह (निवल)	-5,105	1,028	3,242	7,495	1,026	-2,038
III	भूल-चूक	2,689	-1,021	-1,073	364	-668	1007
IV	संपूर्ण शेष	3,826	61,406	17,905	21,550	15,481	20,903
V	आरक्षित परिवर्तन	-3,826	-61,406	-17,905	-21,550	-15,481	-20,903
	[वृद्धि (-)/कमी (+)]						

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक
पी-प्रारंभिक

और पेट्रोलियम अपरिष्कृत एवं उत्पादों में अच्छी निर्यात वृद्धि, रासायनिक और संबंधित उत्पादों तथा वस्त्र एवं संबद्ध उत्पादों में मामूली वृद्धि परन्तु रत्नों एवं आभूषण में नकारात्मक वृद्धि रही (सारणी 5)

6.19 क्षेत्र (दृष्टि से) वार, 2014-15 और 2015-16 में एकाएक गिरावट के बाद 2015-16 में 46.2 अमेरिकी डालर प्रति बैरल से 2016-17 में 47.6 अमेरिकी डालर प्रति बैरल और 2017-18 में 53.6 अमेरिकी डालर प्रति बैरल तक

अन्तरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत (भारतीय बाजार) बढ़ोत्तरी के कारण मुख्य रूप से पेट्रोलियम तेल और स्नेहक पदार्थों के आयात में 2016-17 में 4.8 प्रतिशत और 2017-18 में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016-17 में अन्य महत्वपूर्ण आयात मदों के बीच, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, अयस्क और खनिज पदार्थ और कृषि एवं संबद्ध उत्पादों को छोड़कर इनमें से अधिकांश उत्पादों में निम्न अथवा नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। पूंजीगत माल के आयात में मामूली वृद्धि हुई यद्यपि परिवहन उपस्कर उप-श्रेणी के मामले में उच्च वृद्धि

सारणी 5: निर्यातों का क्षेत्रवार अंश और वृद्धि दर

क्रम		शेयर (प्रतिशत)			वृद्धिदर (प्रतिशत)		
		2015-16	2016-17	2017-18 (Apr-Nov) (P)	2015-16	2016-17	2017-18 (Apr-Nov) (P)
1	इंजीनियरी संबंधी वस्तुएं	23.1	24.4	25.9	-17.0	11.1	22.4
2	रत्न और आभूषण	15.0	15.7	14.4	-4.8	10.5	-3.8
3	रासायनिक और संबंधित उत्पाद **	14.7	14.2	14.5	0.6	1.6	11.9
	<i>जिसमें</i>						
	मादक और औषधीय शामिल है	6.2	5.8	5.4	9.9	-1.2	-0.7
4	कपड़ा और संबद्ध उत्पाद	13.7	13.0	11.8	-3.2	-0.5	3.8
	<i>जिसमें</i>						
	कपड़ा	5.6	5.2	4.9	-8.5	-2.3	5.9
	परिधान	8.1	7.8	6.9	0.8	0.7	2.4
5	पेट्रोलियम अपशिष्ट और उत्पाद	11.7	11.4	11.8	-46.2	3.1	17.6
6	कृषि और संबद्ध उत्पाद *	9.9	9.5	9.7	-17.6	0.3	15.0
7	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	2.2	2.1	2.0	-5.3	0.0	4.5
8	समुद्री उत्पाद	1.8	2.1	2.7	-13.5	23.8	29.5
9	अयस्क और खनिज	0.8	1.2	1.0	-16.4	61.6	12.9
10	चर्म और चर्म उत्पाद	2.1	1.9	1.9	-10.3	-4.4	0.9
	अन्य निर्यातों सहित कुल निर्यात	100.0	100.0	100.0	-15.5	5.2	11.2

स्रोत: वाणिज्य विभाग के डाटाबेस से परिकल्पित पी. अनंतिम
टिप्पणियां: पौधरोपण सहित प्लास्टिक और रबड़ उत्पादों सहित

दर्ज की गई (तालिका 6) 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में सभी बड़े सेक्टरों में भी वृद्धि हुई, यहां तक कि पूंजीगत माल के आयात में भी वृद्धि हुई जिनकी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यकता भी है और यह वृद्धि 11.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

व्यापार नीति

6.20 व्यापार नीति में दो महत्वपूर्ण विकास विदेश व्यापार नीति पटल (एफटीपी) की मध्यावधिक समीक्षा और दिसम्बर

2017 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की नवीन बहुपार्श्विक वार्ताएं रही हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें व्यापार संभारतंत्र और प्रतिपाटन (एंटी डम्पिंग) कार्रवाइयों से संबंधित कुछ परिवर्तन भी हैं।

विदेश व्यापार नीति मध्यावधिक समीक्षा और परवर्ती व्यापार से संबद्ध नीतियां

6.21 5 दिसम्बर, 2017 को जारी की गई विदेश व्यापार नीति की मध्यावधिक समीक्षा में भारत के व्यापार सेक्टर

सारणी 6: आयातों की क्षेत्रवार अंश और वृद्धि दर

क्रम	क्षेत्र (सेक्टर)	शेयर (प्रतिशत)			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
		2015-16	2016-17	2017-18 (Apr-Nov) (P)	2015-16	2016-17	2017-18 (Apr-Nov) (P)
1	पेट्रोलियम तेल और स्नेहक पदार्थ	21.8	22.6	22.0	-40.0	4.8	21.9
2	पूंजीगत वस्तुएं	21.1	20.9	19.2	-2.5	0.1	11.3
	मशीनरी	8.7	8.5	8.3	3.7	-1.4	16.8
	आधार धातुएं	6.5	5.6	6.0	-8.7	-12.8	26.5
	परिवहन उपस्कर	4.0	5.1	3.3	0.7	27.1	-18.3
3	रत्न और आभूषण	14.8	14.0	16.8	-9.4	-4.9	53.6
	जिसमें						
	सोना	8.3	7.2	7.8	-7.7	-13.4	46.4
	मोती और अर्ध कीमती पत्थर	5.3	6.2	7.6	-11.2	18.6	47.7
	चांदी	1.0	0.5	0.8	-17.3	-50.9	90.0
4	रासायनिक और संबंधित उत्पाद **	13.3	12.4	12.7	-4.2	-5.8	16.3
	जिसमें						
	जैव रसायन	2.5	2.6	2.6	-15.2	2.7	23.8
	उर्वरक	2.1	1.3	1.3	9.1	-37.8	-5.0
5	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	10.5	10.9	11.4	8.6	4.8	29.7
6	कृषि और सम्बद्ध उत्पाद*	5.7	6.3	5.6	7.7	11.4	11.4
7	अयस्क और खनिज पदार्थ	5.4	5.6	6.6	-23.2	4.6	55.6
	जिसमें						
	कोयला, कोक और संपीडित खंड आदि	3.6	4.1	4.8	-23.2	15.3	58.1
	अन्य आयातों सहित कुल आयात	100.0	100.0	100.0	-15.0	0.9	22.4

स्रोत: वाणिज्य विभाग के डाटाबेस से परिकलित पी: अनंतिम

* समुद्री उत्पादों और पौधरोपण सहित ** प्लास्टिक और रबड़ उत्पादों सहित

बॉक्स 1: विदेश व्यापार नीति की मध्यावधिक समीक्षा की महत्वपूर्ण बातें (हाईलाइट)/नीतियां

- कपड़ों के दो उपक्षेत्रों अर्थात रेडीमेड गार्मेंट और मेड अप गार्मेंट के लिए एमईआईएस (भारत से वाणिज्यिक वस्तु निर्यात स्कीम) प्रोत्साहन को 2743 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन राशि लगाकर 2% से बढ़ाकर 4% किया गया।
- निर्यातों के लिए एमएसएमईएस/श्रम गहन उद्योगों द्वारा 4576 करोड़ रुपये की मौजूदा एमईआईएस प्रोत्साहन राशि में 2% की वृद्धि की गई।
- सेवा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, एमईआईएस (भारत से सेवा निर्यात स्कीम) प्रोत्साहन राशि को व्यापार, विधिक, लेखाकरण, वास्तुशास्त्रीय इंजीनियरी शिक्षा, अस्पताल, होटलों और रेस्तराओं जैसी अधिसूचित सेवाओं के लिए 2% वृद्धि की गई है जिसकी रकम 1140 करोड़ रुपये है।
- ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की वैधता अवधि का 18 माह से बढ़ाकर 24 माह की गई है जिससे कि जीएसटी ढांचे में उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सके। स्क्रिप्स के अंतरण/बिक्री पर जीएसटी दर को घटाकर शून्य कर दिया गया है, जो पहले 12% थी।
- स्व घोषणा से शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क रहित आगतों की अनुमति देने के लिए विश्वास आधारित नई अनुसमर्थन स्कीम लागू की गई। इस स्कीम के अंतर्गत, निर्यात उत्पादों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले आदानों के लिए मानक समिति का अनुसमर्थन प्राप्त करने के बजाय, निर्यातक शुल्क रहित कच्ची सामग्रियों/इनपुट की आवश्यकता को स्वतः प्रमाणित करेंगे और डीजीएफटी से प्रमाणीकरण लेंगे। यह स्कीम प्रारंभिक तौर पर प्राधिकृत आर्थिक आपरेटरों के लिए उपलब्ध होगी।
- शिकायत निपटान के लिए contact @ DGFT सेवा: विदेशी व्यापार से संबंधित सभी मामलों के समाधान के लिए निर्यातकों और आयातकों के लिए एकल खिड़की संपर्क प्वाइंट के तौर पर डीजीएफटी का वेबसाइट (www.dgft.gov.in) को सक्रिय किया गया है।
- निर्यातकों और आयातकों के लिए सीमापार व्यापार में सुधार पर ध्यान देने के लिए उनके निर्यात से संबंधित समस्याओं, निर्यात बाजार में पैठ बनाने के लिए और नियामक अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए एक व्यावसायिक टीम बनाई गई है।
- पॉलिसियों में परिवर्तन करते हुए, मौजूदा कार्यवाहियों में सुधार करते हुए, अवरोधों और अंतरालों और इस सेक्टर में प्रौद्योगिकी उपयोग द्वारा संभारिकी के एकीकृत विकास के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन के विकास और समन्वय के लिए वाणिज्य विभाग में नया संभारिकी प्रभाग बनाया गया है।
- स्पष्टता के लिए पूंजीगत माल की एक नकारात्मक सूची जारी की गई है जिसको ईपीसीजी (पूंजीगत माल पर निर्यात प्रोत्साहन) स्कीम के अंतर्गत अनुमत नहीं किया गया है।
- रियायती और पूर्ण शुल्क पर निर्यात उन्मुख इकाई (ई.ओ.यू.) से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी.टी.ए.) में बिक्री की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और इसलिए डी.टी.ए. की हकदारी की सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप मोटर कारों, मादक द्रव्यों, पुस्तकों और चाय की डी.टी.ए. बिक्री पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटा लिया गया है।
- मरम्मत/नवीकरण/पुनः कंडीशनिंग या पुनः इंजीनियरी के उद्देश्य से आयात किए जाने वाले पुराने मालों को निःशुल्क कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप मरम्मत सेवा के क्षेत्र में रोजगार का सृजन सहज हो जाएगा।
- निवेशों पर जी.एस.टी. के अग्रिम भुगतान के प्रावधान के कारण निर्यातकों के कार्यशील पूंजी को अवरूद्ध कर दिए जाने के मामले का निपटारा किया जा चुका है। पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन (ई.पी.सी.सी.) योजना के अग्रिम प्राधिकार के तहत ई.ओ.यू. के 100% निर्यातकों के लिए जी.एस.टी. का अग्रिम भुगतान किए बिना विदेशी और अपने देश के प्रदायकों से निर्यात के लिए निवेशों/पूंजीगत मालों को प्राप्त करने के लाभ को विस्तृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2018 से इन योजनाओं को प्रचालन योग्य बनाने के लिए 1 अप्रैल, 2018 से ई-वैलेट शुरू की जाएगी।
- 15 दिसंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने चमड़ा और फुटवियर के क्षेत्र में रोजगार का सृजन करने के लिए एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया है। इस पैकेज के अन्तर्गत 2600 करोड़ रुपए के अनुमोदित व्यय से 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों में “भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम” की केंद्रीय योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना से चमड़े के क्षेत्र के लिए अधिसंरचना का विकास होगा, चमड़े के क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण संबंधी समस्या का समाधान होगा, अतिरिक्त निवेश कर पाना सुविधाजनक हो जाएगा, रोजगार उत्पन्न होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। फुटवियर, चमड़ा और सहायक उपकरण के क्षेत्र में 3 वर्षों में 3.24 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने और संचयी प्रभाव से 2 लाख रोजगार सुलभ कराने में सहायता करने की क्षमता इस विशेष पैकेज में है।

स्रोत: वाणिज्य विभाग की निविष्टियों पर आधारित।

की सहायता करने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्रवाइयां की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 15 दिसम्बर, 2017 को चमड़ा एवं फुटवियर सेक्टर में रोजगार सृजन के लिए एक विशेष पैकेज का सरकार द्वारा अनुमोदन दिया गया था, उससे भी इस सेक्टर के निर्यातकों को मदद मिलने की आशा है (बॉक्स-1)

बहु-पक्षीय व्यापार वार्ताएं

6.22 विश्व व्यापार संघ का ग्यारहवाँ मंत्रीस्तरीय सम्मेलन बिना किसी मंत्रीय घोषणा अथवा टोस परिणाम के ही समाप्त हो गया, फिर भी सभी का यह मत था कि इसे पूर्ण स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ बहुत ही अच्छी तरह से संचालित किया गया और इस प्रक्रिया में सभी को अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

6.23 एम.सी-11 से पहले खाद्य सुरक्षा और कृषि संबंधी अन्य मुद्दों के संबंध में स्थायी समाधान के निर्णयों की उम्मीद की जा रही थी। दुर्भाग्यवश मौजूदा डब्ल्यू.टी.ओ. अधिदेश और नियमों पर आधारित कृषि सुधारों के विरुद्ध एक सदस्य के द्वारा किए गए प्रबल विरोध के कारण कृषि के संबंध में ऐसा गतिरोध हुआ कि बिना किसी परिणाम के, यहां तक कि अगले दो वर्ष के लिए कोई कार्यक्रम बनाए बिना ही यह सम्मेलन समाप्त हो गया। तथापि, मौजूदा अधिदेश और निर्णय यह सुनिश्चित करते हैं कि यह कार्य आगे चलता रहेगा और सदस्य खाद्य सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए सरकारी भंडार संबंधी स्थायी समाधान, कृषि संबंधी विशेष सुरक्षा और कृषि संबंधी घरेलू सहायता जैसे मुद्दों पर कार्य करते रहेंगे। लिए गए कुछ निर्णयों में सब्सिडी संबंधी विषयों पर कार्यक्रम शामिल था, जिसका उद्देश्य एम.सी.-12 तक निर्णय पर पहुँचना था। ई-कॉमर्स संबंधी मौजूदा कार्यक्रम के गैर-वार्ताकारी अधिदेश

को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। निवेश को सुसाध्य बनाने, एम.एस.एम.ई., महिला संबंधी मुद्दों एवं व्यापार जैसे नए मुद्दे, जिनके लिए अधिदेश या सर्वसम्मिति का अभाव है, के संबंध में मंत्री-स्तरीय निर्णयों को आगे नहीं ले जाया गया।

6.24 मंत्री सम्मेलन (एमसी 11) के दौरान भारत डब्ल्यू टी ओ के मूल सिद्धांतों सहित बहुपक्षीय नियम आधारित परस्पर सहमति से निर्णय लेने, एक स्वतंत्र एवं विश्वसनीय विवाद समाधान और अपीलिय प्रक्रिया और विकास की केंद्रीयता पर अडिग रहा जिसमें दोहा विकास एजेंडा (डीडीए) और सभी विकासशील देशों के लिए विशेष और विविध स्तरीय व्यवहार संबंधी व्यवस्था भी निहित है।

व्यापार संबंधित संभार तंत्र

6.25 एक अनुमान के मुताबिक भारतीय संभार तंत्र उद्योग वर्ष 2016-17 में लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का रहा होगा तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान यह उद्योग 7.8% की वार्षिक चक्रवर्धी वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के प्रभाव पर विचार करते हुए भारतीय संभार तंत्र बाजार के वर्ष 2019-20 में वार्षिक वृद्धि दर 10.5% के हिसाब से लगभग 215 बिलियन अमेरिकी डालर पहुँचने की उम्मीद है। निर्यात में वृद्धि तभी संभव है जब संभार व्यवस्था उन्नत हो अर्थात् यदि अप्रत्यक्ष संभार लागत में 10% की कमी कर दी जाए तो निर्यात में लगभग 5-8% की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। भारत ने “संभार कार्य निष्पादन सूचकांक” में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। भारत 2014 में 54 स्थान पर था जबकि 2016 में छलांग लगाते हुए 35 स्थान पर पहुँच गया (सारणी 7) हाँलाकि सिंगापुर (रैंक 5), दक्षिण अफ्रीका (20), ताइवान

सारणी 7: संभार कार्य-निष्पादन सूचकांक: भारत की रैंकिंग

	2007	2010	2012	2014	2016
समग्र एलपीआई रैंकिंग	39	47	46	54	35
सीमा शुल्क और सीमा प्रबंधन की दक्षता	47	52	52	65	38
व्यापार और परिवहन अवसंरचना की गुणवत्ता	42	47	56	58	36
प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर शिपमेंट की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना	40	46	54	44	39
संभार सेवाओं की सक्षमता और गुणवत्ता	31	40	38	52	32
परेषणों को ट्रैक एवं ट्रेस करने की योग्यता	42	52	54	57	33
समय पर सुपुर्दगी	47	56	44	51	42

स्रोत: विश्व बैंक एलपीआई सांख्यिकी (2016)

बॉक्स 2: संभार तंत्र: चुनौतियां और सुझाई गई कार्य योजना

कुछ प्रमुख चुनौतियां

संभार तंत्र की उच्च लागत घरेलू तथा वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव

- अननुकूल परिवहन मिश्र (रोडवेज 60% रेलवे 30%) और अदक्षतापूर्ण वाहन मिश्र
- अविकसित सामग्री संभाल अवसंरचना तथा खण्डित भण्डारण
- बोझिल एवं दोहरी प्रक्रियाओं सहित विभिन्न प्रक्रियात्मक जटिलताओं वाले अनेक विनियामक/नीति निर्माता निकाय
- उच्च ठहराव समय तथा विभिन्न परिवहन स्वरूपों के बीच माल के निर्बाध संचलन का अभाव

सुझाई गई कार्य-योजना

- संभरण कार्यों में उच्च पारदर्शिता लाने व दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत संभारतंत्र नीति तैयार करना
- संभरण संबंधी समस्त मामलों के लिए एक एकल केंद्र के रूप में एकीकृत आईटी प्लेटफार्म का विकास करना। यह पोर्टल रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, नागरिक उड्डयन, सीबीईसी, राज्य परिवहन विभागों आदि के साथ जुड़ा होगा तथा एक संभरण विपणन-स्थल के रूप में कार्य करेगा।
- प्रलेखन में सरलता, तीव्रतर क्लियरेंस, डिजिटाइजेशन, करना।
- वर्ष 2022 तक, संभार लागत को जीडीपी के 10% से कम करना
- बहु वाहन मिश्र आधारित संभार पार्क (एमएमएलपी), कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) और इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) जैसी संभारतंत्र अवसंरचना की स्थापना के लिए तेजी से स्वीकृति देना
- सेवा प्रदाताओं के लिए पेशेवर मानकों एवं प्रमाणन का प्रारंभ करना
- उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना जैसे उच्च तकनीकी स्कैनिंग उपस्कर, आरएफआईडी, जीपीएस, ईडीआई, संपूर्ण संभार नेटवर्क में ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली का प्रयोग आदि।
- देश में संभार कौशल विकास का संवर्धन करना तथा संभार सेक्टर में वर्ष 2022 तक 40 मिलियन तक नौकरियां बढ़ाना है।

स्रोत: संभारिकी प्रभाग, वाणिज्य विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित।

(25) और चीन (27) जैसे देशों की तुलना में भारत को अभी काफी आगे तक जाना है।

डॉपिंग-रोधी उपाय

6.26 वैश्विक मंदी के बाद के विश्लेषण में डॉपिंग की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। देश में माल की डॉपिंग के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों, घरेलू उद्योग को इससे होने वाली क्षति तथा डॉपिंग और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच अनुषंगी संबंध के आधार पर भारत सरकार डॉपिंग रोधी अन्वेषण कराती है। वर्ष 2016 में, भारत सहित समस्त देशों द्वारा 300 डॉपिंग रोधी अन्वेषण प्रारंभ कराए गए जिनमें से भारत के सर्वाधिक 69 अन्वेषण थे और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (37) और अर्जेंटीना (25) थे (सारणी 8)।

6.27 वर्ष 2017-18 (दिसंबर के अंत तक) के दौरान डीजीएडी ने 24 उत्पादों के आयात के संबंध में एन्टी डॉपिंग जांच शुरू की, 3 एन्टी डॉपिंग जांचों में प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किए, 35 एन्टी डॉपिंग जांचों में अंतिम निष्कर्ष जारी किए

और एक एंटी डॉपिंग शुल्क से बचने के प्रयास पर अंतिम निष्कर्ष जारी कर दिए हैं। जिन उत्पादों पर एंटी डॉपिंग ड्यूटी लागू की गई है वे रसायन और पेट्रो रसायन के समूह के उत्पादों, इस्पात एवं अन्य धातुओं के उत्पादों और रबड़ अथवा प्लास्टिक उत्पादों के अन्तर्गत आते हैं। इन जांचों में चीन, ईरान, सउदी अरब, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया, थाईलैंड, नार्वे, तुर्की, बंगला देश, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और ताइवान देश शामिल हैं। डॉप किए गए सर्वाधिक उत्पादों की मात्रा चीन से आयी है।

विदेशी मुद्रा भंडार

6.28 दिसंबर 2017 के अन्त तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 409.4 बिलियन अमेरिकी डालर के साथ अब तक के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में दिसम्बर 2016 के अंत से (358.9 बिलियन अमेरिकी डालर) से दिसम्बर 2017 के अंत तक (409.4 बिलियन अमेरिकी डालर) वर्षानुगत आधार पर 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मार्च 17 के अंत (370.0 बिलियन अमेरिकी डालर)

से दिसम्बर 2017 के अंत तक 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित परिसंपत्तियों के मूल्य परिवर्तन के साथ-साथ बीओपी आधार पर भंडार में परिवर्तन के कारण विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर में परिवर्तन हो सकता है। भुगतान शेष के आधार पर अर्थात् मूल्य निर्धारण के प्रभावों, को छोड़कर विदेशी मुद्रा भंडार में वर्ष 2016-17 की पहली छमाही के दौरान 15.5 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि की तुलना में 2017-18 की पहली छमाही के दौरान 20.9 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 की पहली छमाही के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार (मूल्य निर्धारण प्रभावों रहित) में 30.3 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि हुई जबकि पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान 11.8 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि हुई थी। मूल्य निर्धारण प्राप्ति में बड़ी मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डालर में हास दिखाता है। वर्ष 2017 की पहली छमाही के दौरान 9.3 बिलियन अमेरिकी डालर की राशि की कमी आई जबकि पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान 3.7 बिलियन अमेरिकी डालर का घाटा हुआ था (सारणी 9)। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आयात कवर मार्च अंत 2017 में 11.3 माह की तुलना में नवंबर 2017 के अंत में 11.1 माह था। समान था। चालू खाते पर घाटे वाली रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे विशाल है और विश्व के सभी देशों में छठा विशालतम है।

मुद्रा विनिमय दर

6.29 वर्ष 2017-18 (दिसंबर 17 तक) के दौरान अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में वृद्धि होती रही है, हां सितंबर 17 के दौरान बीच-बीच में गिरावट भी दर्ज की गई है। दिसंबर 2017 के दौरान रुपया 2.5 प्रतिशत सुदृढ़ होकर 64.24 रुपए प्रति अमेरिकी डालर के स्तर पर पहुंच गया जबकि विदेशी पोर्ट फोलियो प्रवाह और एफडीआई दोनों के उल्लेखनीय पूंजी प्रवाह की सहायता से मार्च 2017 में रुपया 65.88 रुपए प्रति डालर के स्तर पर था। उत्प्लावक पूंजी प्रवाह के लिए मुख्यतः भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों के साथ-साथ संवर्धित व्यापक आर्थिक परिस्थितियां जिम्मेदार रहीं। इस अवधि के दौरान न्यूनतम अस्थिर ई-एम मुद्राओं में से एक रुपया रहा और प्रति डालर 63.63 से लेकर 65.76 के बीच लेन देन होता रहा।

6.30 औसतन अमेरिकी डालर (अप्रैल-दिसंबर 2017) के साथ साथ अन्य सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपए के मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई। गत राजकोषीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (चित्र 8) अप्रैल-दिसम्बर 2017 की अवधि के दौरान रुपए में पाउंड स्टर्लिंग मुकाबले लगभग 6.0 प्रतिशत, यूरो के मुकाबले 0.2 प्रतिशत और जापानी येन के मुकाबले में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सारणी 8 : डंपिंग-रोधी उपायों के कुछ मुख्य प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए अन्वेषण

Country	India	USA	EU	Brazil	Argentina	Australia	China	All Countries including others
2009	31	20	15	9	28	9	17	217
2010	41	3	15	37	14	7	8	173
2011	19	15	17	16	7	18	5	165
2012	21	11	13	47	12	12	9	208
2013	29	39	4	54	19	20	11	287
2014	38	19	14	35	6	22	7	236
2015	30	42	12	23	6	10	11	229
2016	69	37	14	11	25	17	5	300
1995-2016	839	606	493	403	348	316	234	5286

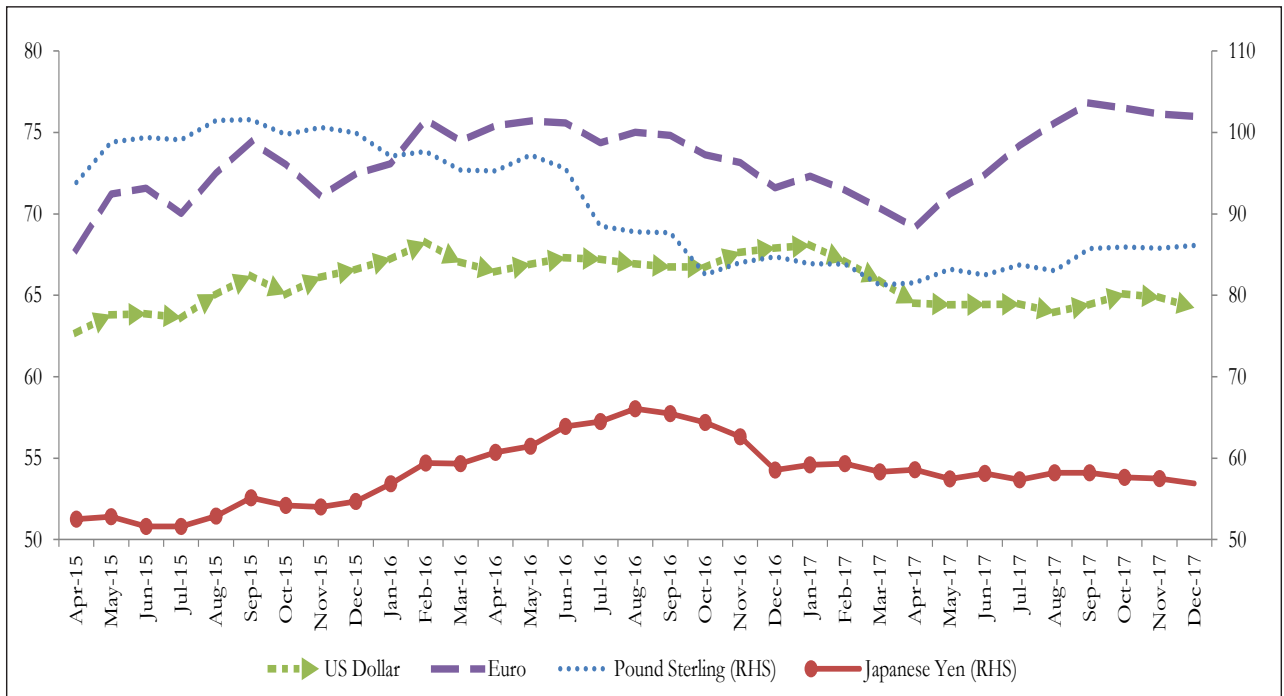
Source: WTO

सारणी 9 : विदेशी मुद्रा भंडारों में परिवर्तन का सारांश (बिलियन अमेरिकी डालर)

वर्ष	वित्तीय वर्ष के अंत (मार्च के अंत में) विदेशी मुद्रा भंडार	मुद्रा भंडार में कुल वृद्धि (+)/ गिरावट (-)	बीओपी के आधार पर भंडार में वृद्धि (+) गिरावट (-)	मूल्य निर्धारण प्रभाव के कारण भंडार में वृद्धि/गिरावट
2007-08	309.7	110.5	92.2	18.3
2008-09	252.0	-57.7	-20.1	-37.6
2009-10	279.1	27.1	13.4	13.7
2010-11	304.8	25.8	13.1	12.7
2011-12	294.4	-10.4	-12.8	2.4
2012-13	292.0	-2.4	3.8	-6.2
2013-14	304.2	12.2	15.5	-3.3
2014-15	341.6	37.4	61.4	-24.0
2015-16	360.2	18.5	17.9	0.6
2016-17	370.0	9.8	21.6	-11.8
2016-17 (H1)	372.0*	11.8	15.5	-3.7
2017-18 (H1)	400.2*	30.3	20.9	9.3

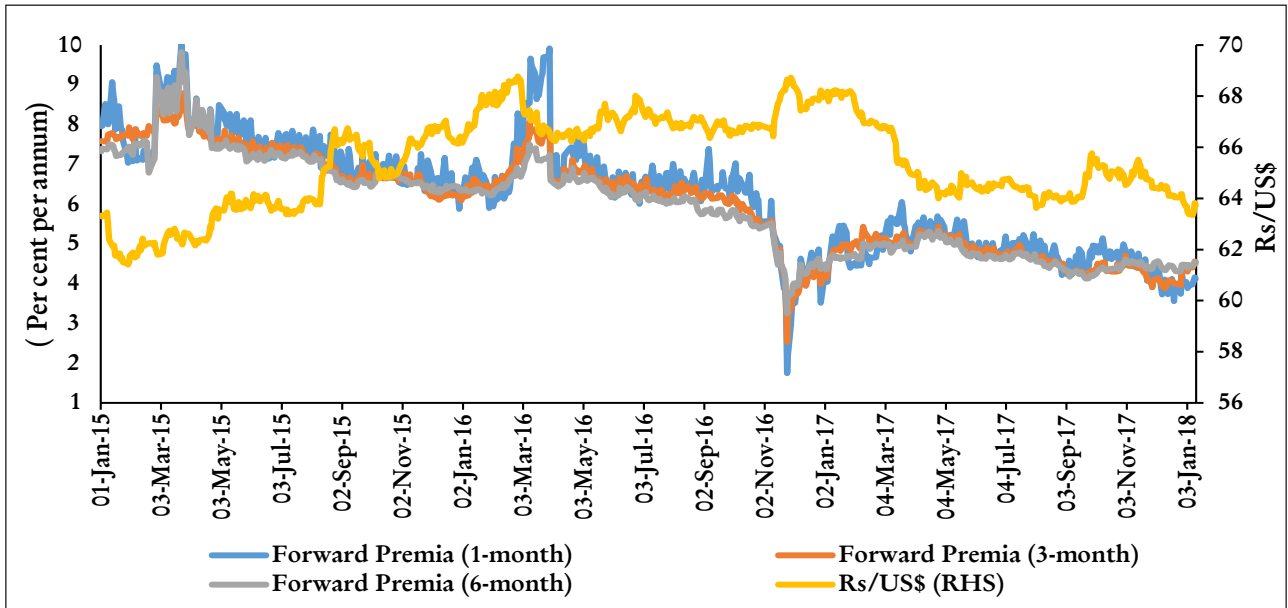
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई H1 अप्रैल से सितंबर)

चित्र 8 : अमेरिकी डालर यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन के मुकाबले रुपए में उतार-चढ़ाव



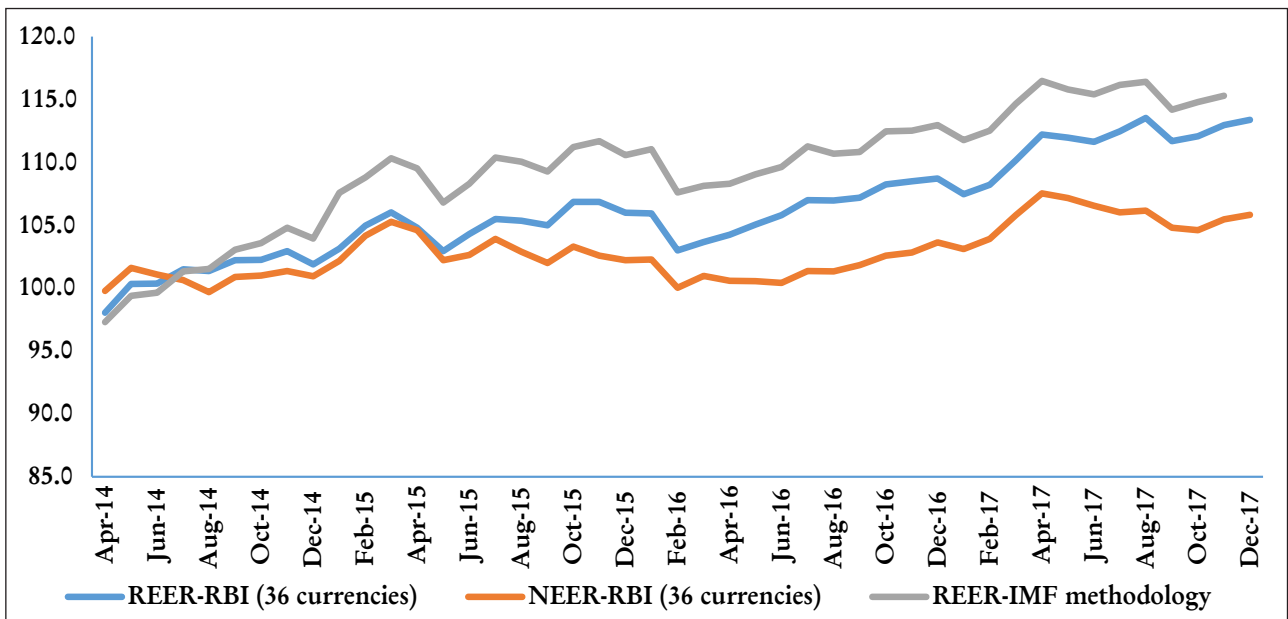
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा पर आधारित

चित्र 9: फॉरवर्ड प्रीमिया का रूझान और संदर्भ दर (स्पॉट)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

चित्र 10: आरईईआर में संकेतों में उतार चढ़ाव, एनईईआर: (2014 = 100)



स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: आरईईआर आईएमएफ का परिकलन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनाई गई पद्धति से किया जाता है।

6.31 फॉरवर्ड प्रीमिया में सामान्यतः वर्ष 2017-18 के दौरान (11 जनवरी, 2018 तक), सितम्बर, 2017 और जनवरी, 2018 में कुछ सख्ती को छोड़कर, मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीति दर में कटौती के ठीक बाद भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दर अंतर के सीमित होने और यू एस फंड की ब्याज दर में वृद्धि होने के कारण रूझान में नरमी दिखाई

दी। 6 माह का फॉरवर्ड प्रीमिया, जो मार्च, 2017 के अंत में 4.9 प्रतिशत पर था, 11 जनवरी 2018 को गिरकर 4.5 प्रतिशत रह गया और इस अवधि के दौरान 4.2 प्रतिशत से 5.3 प्रतिशत की रेंज में चला गया (चित्र 9)।

6.32 36 और 6 मुद्रा समूहों में से मौद्रिक प्रभावी वि. निमय दर (व्यापार-मूल्यांकन) के संदर्भ में, रुपये के मूल्य

सारणी 10 : भारत के महत्वपूर्ण विदेशी ऋण सूचक (प्रतिशत)

वर्ष	विदेशी ऋण बिलियन अमेरिकी डालर	विदेशी ऋण में वृद्धि (%)	सकल घरेलू उत्पाद से कुल विदेशी ऋण का अनुपात	ऋण सेवा अनुपात	कुल विदेशी ऋण से लिए रियायती ऋण का अनुपात	कुल विदेशी ऋण के लिए विदेशी निमय रिजर्व	विदेशी विनिमय रिजर्व के लिए अल्पावधिक विदेशी ऋण	कुल ऋण पर अल्पावधिक विदेशी ऋण	कुल ऋण पर अल्पावधिक ऋण (शेष भुगतान तिथि)	विदेशी वि. निमय प्रारक्षित निधि के लिए अल्पावधिक ऋण (शेष भुगतान तिथि)
2012-13	409.4	13.5	22.4	5.9	11.1	71.3	33.1	23.6	42.1	59.0
2013-14	446.2	9.0	23.9	5.9	10.4	68.2	30.1	20.5	39.7	58.2
2014-15	474.7	6.4	23.9	7.6	8.8	72.0	25.0	18.0	38.5	53.5
2015-16	485.1	2.2	23.5	8.8	9.0	74.3	23.1	17.2	42.7	57.4
2016- 17 R	471.8	-(2.7)	20.2	8.3	9.3	78.4	23.8	18.6	41.5	52.9
End-September 2017 P	495.7	5.1	*	*	9.1	80.7	23.2	18.7	41.7	51.7

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट : R = रिजर्व, = P प्रोविजनल अल्पावधिक ऋण मूल भुगतान तिथि पर आधारित होता है।

ऋण सेवा अनुपात चालू खाता प्राप्तियों (सरकारी अन्तरणों का निवल) के लिए सकल ऋण सर्विस भुगतानों का अनुपात होता है।

में अप्रैल-दिसम्बर 2017-18 में क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि इसमें दिसम्बर, 2017 में, मार्च 2017 में इसके औसत स्तर से क्रमशः 2.0 प्रतिशत और 0.03 प्रतिशत वृद्धि भी दिखाई दी है।

6.33 36 मुद्राओं के एक समूह के संदर्भ में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (व्यापार भारित) के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर 2017 में रुपए में वर्ष 2016-17 की संगत अवधि की तुलना में 5.2 प्रतिशत की कीमत वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आरईईआर पद्धति के अनुसरण से, अप्रैल-नवम्बर 2017 के दौरान 4.5 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई। यद्यपि इस दौरान रुपया व्यापक रूप से स्थिर बना रहा तथापि आरईईआर की मूल्यवृद्धि संकेत करती है कि भारत के निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में हल्की सी कमी आ गई है। (चित्र 10)।

विदेशी ऋण

6.34 भारत का विदेशी ऋण मार्च, 2017 के अंत से सितंबर 2017 के अंत तक 5.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 495.7 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया, जबकि जून, 2017 के अंत से इसमें 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मार्च 2017 की तुलना में सितंबर 2017 के अंत में प्रमुख दीर्घावधि ऋण में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है हालांकि, इसका भाग 81.3 प्रतिशत रहा जोकि 81.4 प्रतिशत की मौजूदा स्थिति की तुलना में कमोवेश समान ही है। दीर्घावधि ऋण में वृद्धि प्राथमिक तौर पर घरेलू पूंजी बाजार (जिसमें वाणिज्यिक उधारियां भी शामिल हैं) के ऋण खण्ड के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में

वृद्धि के कारण हुई है। लघु अवधि ऋण में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से व्यापार संबंधी क्रेडिट में वृद्धि के कारण हुई। कुल ऋण में सरकारी (संप्रभु) ऋण की हिस्सेदारी में मार्च 2017 के अंत में 19.4 प्रतिशत की तुलना में सितंबर, 2017 के अंत में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो के बढ़ते स्तर को दर्शाने वाले अन्य सरकारी विदेशी ऋण अवयव के कारण हुई।

6.35 कुल विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा कवर में मार्च, 2017 के अंत में 78.4 प्रतिशत की तुलना में सितंबर, 2017 के अंत में 80.7 प्रतिशत हो गया। मूल परिपक्वता के अल्पकालिक ऋणों का विदेशी मुद्रा भंडार के साथ अनुपात मार्च अंत 2014 के 23.8 प्रतिशत से घट कर सितंबर अंत 2017 में 23.2 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा भंडारों की अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा फलित लघु अवधि ऋण का अनुपात 52.9 प्रतिशत से गिरकर 51.7 प्रतिशत आ गया। वर्ष के दौरान सेवा सविदागत देयताओं के लिए नकदी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी कुल विदेशी ऋण पर शेष भुगतान तिथि के अनुसार अल्पावधिक ऋण का अनुपात मार्च 2017 के अंत में 41.5 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2017 के अंत में कुल मिलाकर कमोवेश 41.7 प्रतिशत था (सारणी 10)। मार्च 2017 की अपेक्षा सितम्बर 2017 में अन्य मुद्राओं के मुकाबले यूएस डालर में मूल्य हास होने के कारण मूल्यांकन हानि 1.4 बिलियन अमेरिकी डालर थी जिसका निहितार्थ यह है कि मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर विदेशी ऋण 495.7 बिलियन अमेरिकी

डालर के बजाय 494.3 बिलियन अमेरिकी डालर ही रहा होगा।

6.36 विश्व बैंक के डेटा पर आधारित विदेशी ऋण स्थिति की अंतर्राष्ट्रीय तुलना यह दर्शाती है कि वर्ष 2016 में 20 शीर्ष विकासशील ऋणी देशों में भारत की सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) में 20.4 प्रतिशत विदेशी ऋण स्टॉक अनुपात चीन के 12.8 प्रतिशत अनुपात के बाद दूसरा सबसे कम अनुपात था। विदेशी ऋण के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में, भारत की स्थिति पांचवीं सबसे बड़ी और भारत की ऋण सर्विस दर आठवीं सबसे कम दर हैं। विश्व बैंक के डेटा के अनुसार, यद्यपि भारत विकासशील देशों में तीसरा सबसे बड़ा ऋणी देश (चीन और ब्राजील के बाद) है, और कुल ऋण में अल्पावधिक ऋण का भारत का हिस्सा वर्ष 2017 की पहली तिमाही (मार्च को समाप्त) और 2017 की दूसरी तिमाही (जून को समाप्त) में चीन के क्रमशः 59.0 प्रतिशत और 60.1 प्रतिशत की तुलना में केवल 18.6 प्रतिशत और 18.3 प्रतिशत ही है। भारत विश्व के शीर्ष ऋणी देशों

(विकसित और विकासशील देश सहित) में नहीं है और जून 2017 के अंत में यह छब्बीसवें स्थान पर है।

निष्कर्ष

6.37 इस वर्ष में और आने वाले वर्ष में भारत के विदेशी क्षेत्र के लिए संभावनाएं विश्व व्यापार वर्ष 2016, में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 में क्रमशः 4.2 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत होने से उज्वल प्रतीत होती हैं, प्रमुख भागीदार (पार्टनर) देशों का व्यापार सुधर रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की निर्यात वृद्धि भी उच्चतर होती जा रही है। तेल की कीमतों में वृद्धि के जोखिम नकारात्मक पहलू है जिन पर कुछ बढोत्तरी के बाद नियंत्रण कर लिया गया है। तथापि इसके कारण धन प्रेषणों का उच्चतर अंतरप्रवाह भी हो सकता है जिसका बढ़ना आरंभ हो चुका है। सरकार को जीएसटी, संभार तांत्रिकी और व्यापार सुगमता जैसी सहायक नीतियों से और भी मदद मिल सकेगी।